

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2351
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2024

सुगम्य भारत अभियान

2351. श्री बी. के. पार्थसारथी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आन्ध्र प्रदेश में सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने सरकारी भवनों, परिवहन प्रणालियों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को सुगम्य बनाया गया है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में सुगम्य भारत अभियान के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;
- (ग) क्या सरकार ने योजना शुरू किए जाने के समय से इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कोई लेखा परीक्षा कराई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) आन्ध्र प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी अवसंरचना और सेवाओं की पहुंच में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा की गई भावी योजनाओं/पहलों और मौजूदा नीतियों में संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों को सक्षम बनाने के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने हेतु सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान का संचालन कर रहा है, जिसका लक्ष्य निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र की सुगम्यता को बढ़ाना है। एआईसी के तहत, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले 38 भवनों की रेट्रोफिटिंग के लिए 14.36 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की 15 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है। राज्य सरकार ने 7.32 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं।

(ग) से (घ) : सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) के लक्ष्यों के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के स्वामित्व वाले 41 भवनों की सुगम्य (पहुंच संबंधी) लेखा परीक्षा की गई। इन भवनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	ऑडिट किए गए भवनों का नाम (आंध्र प्रदेश)
1.	कलेक्ट्रेट, विशाखापट्टनम
2.	प्रगति भवन, एमवीपी कॉलोनी, विशाखापट्टनम
3.	ऑफिस ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, वेलफेयर ऑफ डिफ्रेंटली एबल एंड सीनियर सिटीजन
4.	डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ऑफिस
5.	सोशल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल, जेडपी जंक्शन, महारानीपेटा , विशाखापट्टनम
6.	सोशल वेलफेयर बॉयज हॉस्टल नंबर 11, सीतामाधारा , विशाखापट्टनम
7.	सोशल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल, आनंदपुरम, जीवीएमसी , विशाखापट्टनम
8.	सोशल वेलफेयर बॉयज हॉस्टल, तगरपुवलसा , जीवीएमसी, विशाखापट्टनम
9.	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, गवर्नमेंट आईटीआई, कांचरापालम
10.	ट्राफ्ट्समैन सिविल लैब, गवर्नमेंट आईटीआई, कांचरापालम
11.	आर एंड एसी, प्लम्बर और पेंटर बिल्डिंग, गवर्नमेंट आईटीआई कंचरापालेम
12.	अल्लीपुरम डिस्पेंसरी, विशाखापट्टनम
13.	बुचिराजुपालेम डिस्पेंसरी, विशाखापट्टनम
14.	मलकापुरा डिस्पेंसरी, विशाखापट्टनम
15.	कपाराडा डिस्पेंसरी, विशाखापट्टनम
16.	विदुत नगर डिस्पेंसरी , विशाखापट्टनम
17.	ज्ञाननपुरम डिस्पेंसरी, विशाखापट्टनम
18.	चाइना वाल्टेयर डिस्पेंसरी, विशाखापट्टनम
19.	आरपी पेटा डिस्पेंसरी, विशाखापट्टनम
20.	श्रीहापुरम एफआरयू, विशाखापट्टनम
21.	अरिलोवा एफआरयू, डिस्पेंसरी , विशाखापट्टनम
22.	सीडीपीओ कार्यालय, आईसीडीएस परियोजना, विशाखापट्टनम
23.	डीएमएसवीके, पाइन एप्पल कॉलोनी, विशाखापट्टनम
24.	वर्किंग वूमेन्स हॉस्टल, सीतामाधारा , विशाखापट्टनम
25.	वर्किंग वूमेन्स हॉस्टल, मारिपालेम , विशाखापट्टनम
26.	सिसु गृह , मरिपालेम , विशाखापट्टनम
27.	आउट पेशेंट लाजुरस ब्लॉक, विक्टोरिया अस्पताल, बुरुजुपेटा , विशाखापट्टनम
28.	पुलिस आयुक्त कार्यालय, सूर्यबाग, विशाखापट्टनम
29.	उप रजिस्ट्रार कार्यालय, भिमिल्ली , विशाखापट्टनम

30.	उप रजिस्ट्रार कार्यालय, गजुवाका , विशाखापट्टनम
31.	नगर निगम आंचलिक कार्यालय, भिमिली , जीवीएमसी, विशाखापट्टनम
32.	किंग जॉर्ज अस्पताल
33.	सरकारी मानसिक देखभाल अस्पताल
34.	सरकारी ईएनटी अस्पताल
35.	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय.
36.	द्वारका बस स्टेशन
37.	मादिलापलेम बस स्टेशन
38.	गजुवाका बस स्टेशन
39.	सिंहाचलम बस स्टेशन
40.	विशाखा स्टील सिटी बस स्टेशन
41.	एमवीपी कॉलोनी बस स्टेशन

(ड.): भारत सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के अंतर्गत बाधा मुक्त वातावरण के सृजन की उप-योजना का कार्यान्वयन करता है जिसके लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त संगठनों/संस्थानों को बाधामुक्त वातावरण के सृजन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।
